श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (राजस्थान) : महोदय, आप मंत्री जी को निर्देश दीजिए कि ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: What is this? ...(*Interruptions*)... I don't want to enter into a debate. ...(*Interruptions*)... Pramod *ji*, in future, I will keep in mind that what you say is not implemented. ...(*Interruptions*)... What is this? आप सब बैठ जाइए। जयराम जी, मेरी जुबान मत खुलवाइए। प्लीज, प्लीज।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, इस पर कानून कब बनेगा?...(व्यवधान)...

MR.CHAIRMAN: I will, in future, keep this in mind that your assurance was a strategy and that is not appreciated. I allowed you on the assurance that you will conform to decorum and discipline but it is not done. ...(*Interruptions*)... You belong to a senior Party. ...(*Interruptions*)... क्या आप मेरा समर्थन कर रहे हैं? Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)... Dr. Ashok Kumar Mittal ...(*Interruptions*)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, हम सदन से वॉकआउट कर रहे हैं।

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber*)

MATTERS RAISED WITH PERMISSION- *Contd.*

Need for Banking Sector reforms in India

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब): सभापति महोदय, आज आपने मुझे सदन के समक्ष एक अत्यंत संवेदनशील विषय को उठाने का मौका दिया। यह विषय हमारे मिडिल क्लास परिवारों के एम्पावरमेंट से संबंधित है। ...(**व्यवधान**)... सर, आरबीआई के अनुसार वर्तमान देश में 16 करोड़ करंट अकाउंट्स हैं और 220 करोड़ सेविंग अकाउंट्स हैं और इन दोनों में 27 लाख करोड़ रुपये डिपोज़िट हैं। जिसमें प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत 53 करोड़ लोगों के अकाउंट्स भी हैं। ये सभी अकाउंट्स गरीब लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के और छोटे व्यापारियों के हैं, जो हमारे देश की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। ...(**व्यवधान**)... इसके अलावा 27 करोड़ रुपये टर्म डिपोजिट, यानी एफडी अकाउंट्स हैं, जिसमें 125 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। यह सराहनीय है कि हमारे आम नागरिक के पास भी अकाउंट है। सर, नागरिक के बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा होता है, उसमें जो आरबीआई की गाइडलाइन्स हैं और जो बैंकों के स्वार्थ की

वजह से आम आदमी को जमा-पूंजी पर उसका जायज़ हक नहीं मिल रहा है, उसको जायज़ ब्याज नहीं मिल रहा है।

महोदय, हमारी समाजवादी प्रजातंत्र में जो आदमी अमीर है और जो 27 करोड़ अकाउंट्स हैं और उनके पास जो एफडीज़ हैं, तो एफडी पर औसतन 7 प्रतिशत ब्याज मिलता है। मुझे हैरानी तब होती है कि जो आदमी गरीब है, जैसे किसान, मजदूर हैं, उन्हें सिर्फ ढाई प्रतिशत औसतन ब्याज मिलता है और जिनके अकाउंट की संख्या 236 करोड़ है। सर, यदि कोई इंसान एक लाख रुपये एफडी में डिपोज़िट करवाता है, तो उसको सात हजार रुपये मिलते हैं, करंट अकाउंट में पैसा जमा करवाता है, तो ज़ीरो मिलता है और सेविंग अकाउंट में करवाता है, तो ढाई हजार रुपये मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि सेविंग अकाउंट में एफडी का एक-तिहाई हिस्सा मिलता है और करंट अकाउंट हो, तो उस पर जीरो मिलता है। आज 236 करोड़ लोग इससे अफैक्टेड हैं। मुझे इस बात को कहते हुए अफसोस होता है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक और सरकारी बैंक दोनों मिलकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं ...(**समय की घंटी**)... और गरीब आदमी के साथ अपने monopolistic status का नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं।

महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 के अंतर्गत public interest में सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को एफडी के इंटरेस्ट के नजदीक लाया जाए। यह मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Ashok Kumar Mittal: Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri Jose K. Mani (Kerala).

Demand to Increase the amount of financial assistance from Rs.1.30 Lakh to Rs. 2 Lakh given under the Scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G)

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्नाटक): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं इस सदन का ध्यान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण' से संबंधित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।)*

महोदय, 2014 से पहले के 29 वर्षों में 'इंदिरा आवास योजना' के माध्यम से केवल 3 करोड़, 25 लाख घर बनाए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार